www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 05 | अंक – 25 | जौनपुर, गुरूवार, 10 सितम्बर 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को मिलेगी रफ्तार, दो महीने में रिपोर्ट होगी तैयार

हिमाचल प्रदेश, (एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से मुलाकात कर प्रदेश में विमानन अवसंरचना विस्तार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है और बेहतर हवाई संपर्क से पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलेगी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि एयरपोर्ट विस्तार के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। इस पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने अधिकारियों को कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार परियोजना की टेक्नो–इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट दो महीने के भीतर अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। साथ ही परियोजना के लिए योग्य सलाहकार की नियुक्ति कर निर्धारित समयसीमा में रिपोर्ट तैयार करने को भी कहा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि यदि रिपोर्ट तय समय में तैयार हो जाती है, तो एयरपोर्ट विस्तार परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से परियोजना की लागत का यथार्थपरक आकलन करने का भी आग्रह किया। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित किए जा रहे हेलीपोर्ट नेटवर्क का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए दूरदराज के इलाकों तक बेहतर पहुंच और आपातकालीन सेवाओं के लिए हेलीपोर्ट बेहद जरूरी हैं। उन्होंने हेलीपोर्ट निर्माण के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने उड़ान योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने पर सहमति व्यक्त की। बैठक में शिमला एयरपोर्ट से नियमित उड़ानों के संचालन पर भी चर्चा हुई।

तीन रेल परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी, पीएम मोदी बोले- पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेलवे की तीन महत्वपूर्ण मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। करीब 10,783 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क का विस्तार होगा। इससे माल और यात्री परिवहन को गति मिलने के साथ पांच राज्यों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि इससे पांच राज्यों में रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी। विशेष रूप से विरासत और वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क का विस्तार होने के साथ लाखों लोगों

को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचेगा। कैबिनेट से मंजूर परियोजनाओं में खड़गपुर–झारसुगुड़ा (बागदेही) चौथी रेल लाइन, कटनी–पेंड्रा रोड चौथी रेल लाइन और बिलासपुर (उसलापुर)–पेंड्रा रोड तीसरी रेल लाइन शामिल हैं। इन परियोजनाओं को वर्ष 2029–30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों को कवर करने वाली इन तीन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में करीब 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इससे लगभग 4,790 गांवों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, जिनकी कुल आबादी करीब 56 लाख है। रेल लाइनों की क्षमता बढ़ने से आवागमन में उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे भारतीय रेल की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता बढ़ेगी। मल्टीट्रैकिंग से ट्रेनों का परिचालन अधिक सुचारू होगा और व्यस्त रेल मार्गों पर भीड़भाड़ कम होगी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र के व्यापक विकास के साथ रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाना भी है। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार की गई हैं।

केंद्र की आंध्र प्रदेश रेल इंफ्रा को एक और बड़ी सौगात, सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जताया आभार

आंध्र प्रदेश, (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की कनेक्टिविटी को बड़ी सौगात देने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। केंद्रीय कैबिनेट ने रेनिगुंटा–अरक्कोणम सेक्शन पर तीसरी और चौथी रेलवे लाइन को मंजूरी दी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने यह प्रतिक्रिया दी। रेनिगुंटा–अरक्कोणम सेक्शन भारतीय रेलवे का एक महत्वपूर्ण 77 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है जो आंध्र प्रदेश के रेनिगुंटा और तमिलनाडु के अरक्कोणम जंक्शन को जोड़ता है। उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आंध्र प्रदेश के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को यह बड़ी मजबूती देने के लिए धन्यवाद कहा। सीएम एन. चंद्रबाबू नायडू 'एक्स' में लिखा, "एनडीए की डबल इंजन, बुलेट–ट्रेन सरकार के तहत आंध्र प्रदेश की कनेक्टिविटी को एक और बड़ा बढ़ावा। केंद्रीय कैबिनेट ने रेनिगुंटा–अरक्कोणम सेक्शन पर तीसरी और चौथी रेलवे लाइन को मंजूरी दी है, जिसमें आंध्र प्रदेश में 46 किलोमीटर का हिस्सा तिरुपति और चित्तूर जिलों को कवर करता है, जिसकी लागत 1,157 करोड़ रुपए है। इससे भीड़भाड़ कम होगी, ट्रेनों की समय पर आवाजाही बेहतर होगी और तिरुपति की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे तीर्थयात्रियों और यात्रियों दोनों को फायदा होगा और माल ढुलाई भी बढ़ेगी।" इससे पहले डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भी प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को आंध्र प्रदेश को लगातार समर्थन देने और राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया था। पवन कल्याण ने पोस्ट में लिखा, "भारतीय रेलवे नेटवर्क में 10,021 करोड़ रुपए की पांच मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं के साथ बड़ा बदलाव होने जा रहा है।

सीईसी ज्ञानेश कुमार का गुजरात दौरा, `रोल से पोल तक पारदर्शिता' पर होगा संवाद

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार आज गुरुवार से भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख के रूप में अपने पहले गुजरात दौरे पर जाएंगे। वे बूथस्तरीय अधिकारियों (बीएलओ), चुनावी साक्षरता क्लब (ईएलसी) के सदस्यों और नागरिकों के साथ संवाद करेंगे। ये संवाद 'रोल से पोल तक पारदर्शिता' विषय पर आधारित होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसके बाद गुजरात की सांस्कृतिक

विरासत से परिचित कराने वाले एक कार्यक्रम के तहत ऐतिहासिक अडालज बावड़ी का दौरा करेंगे। दिन में मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन (एएमए) के परिसर का दौरा करने वाले हैं, जहां वे "भारत में चुनाव करानाकृ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र" विषय पर नागरिकों के साथ बातचीत करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त कल शुक्रवार को गुजरात विश्वविद्यालय के अटल कलाम हॉल में राज्य भर से 500 से अधिक बीएलओ के साथ बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में जमीनी स्तर के चुनाव अधिकारियों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके बाद सीईसी ज्ञानेश कुमार शेला स्थित एयूडीए सभागार में चुनावी साक्षरता क्लबों के 1,000 से अधिक सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में हाल ही में लॉन्च किए गए ईएलसी 2.0 के विजन, मिशन और प्रमुख विशेषताओं का परिचय शामिल होगा। चुनाव आयोग युवा नागरिकों को चुनावी प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों से परिचित कराने के लिए एक मंच के रूप में चुनाव आयोगों को बढ़ावा दे रहा है।

टेड्रोस ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की

नई दिल्ली, (एजेंसी)। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने खास तौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार और गैर–संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की तारीफ की। टेड्रोस ने एशियाई देश तिमोर–लेस्ते की राजधानी दिली में आयोजित डब्ल्यूएचओ दक्षिण–पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत की स्वास्थ्य क्षेत्र की उपलब्धियों और डब्ल्यूएचओ के साथ उसके जारी सहयोग पर चर्चा की। गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर टेड्रोस ने लिखा, "मैंने भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की

और उन्हें देश की स्वास्थ्य सेवाओं में हुई प्रभावशाली प्रगति के लिए बधाई दी। खास तौर पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और गैर–संचारी रोगों के खिलाफ लड़ाई में भारत ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।" उन्होंने 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' पहल की भी सराहना की, जिसके जरिए देशभर में लोगों की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं और जांच सुविधाओं तक पहुंच बढ़ी है। टेड्रोस ने कहा कि लगभग 1.6 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से भारत हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह और आम प्रकार के कैंसर की जांच की सुविधा लोगों के घरों के करीब पहुंचा रहा है। साथ ही जिन मरीजों को आगे इलाज की जरूरत होती है, उनके लिए रेफरल की व्यवस्था भी उपलब्ध है। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने भारत के आशा कार्यकर्ताओं के विशाल नेटवर्क की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये कार्यकर्ता स्वास्थ्य सेवाओं को सीधे लोगों तक पहुंचाने में, खासकर महिलाओं, माताओं और बच्चों की विभिन्न चरणों में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। टेड्रोस ने कहा, "भारत की आशा कार्यकर्ता इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक उनके समुदायों में कैसे पहुंचाई जा सकती हैं। वे गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक माताओं और बच्चों को सहयोग देती हैं।" उन्होंने कहा कि टीकाकरण के दायरे के विस्तार और अस्पतालों या स्वास्थ्य केंद्रों में होने वाले प्रसव की दर 78 से बढ़कर 93 प्रतिशत होने से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में लगातार सुधार देखने को मिला है।

अन्नदाता के साथ अब ऊर्जादाता बनकर देश को रोशन कर रहा - प्रल्हाद जोशी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बुधवार को नई दिल्ली में 7वें एग्रीवोल्टिक्स विश्व सम्मेलन 2026 के पूर्व समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जो किसान हमेशा राष्ट्र को भोजन उपलब्ध कराता रहा है, वही अब अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बनकर देश को रोशन भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि–वोल्टेइक तकनीक किसानों को एक ही भूमि से खाद्यान्न और स्वच्छ ऊर्जा दोनों का उत्पादन करने में सक्षम बना सकती है। प्रल्हाद जोशी ने कहा कि पीएम–कुसुम योजना के अगले चरण में कृषि–वोल्टेइक ऊर्जा के लिए एक समर्पित घटक होगा। इससे किसान खेती के साथ बिजली उत्पादन से भी आय अर्जित

कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें छोटे और सीमांत किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और पंचायतों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भूमि का स्वामित्व किसान के पास ही रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक किसान एक ही एकड़ भूमि से तीन स्रोतों से आय अर्जित कर सकता हैकृफसल की बिक्री, डिस्कॉम को बेची गई बिजली और डीजल पर होने वाली बचत। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों के लिए सौर ऊर्जा से होने वाली आय महज अतिरिक्त आमदनी नहीं, बल्कि आय–सुरक्षा का माध्यम है। यह अच्छे और बुरे दोनों समय में नियमित आय का स्रोत बन सकती है। जोशी ने कहा कि भारत में दुनिया की करीब 18: आबादी रहती है, जबकि विश्व की कुल भूमि का केवल 2.4: हिस्सा भारत के पास है। देश में 85: से अधिक किसान लघु एवं सीमांत किसान हैं, जो 2 हेक्टेयर से कम भूमि पर खेती करते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि–वोल्टेइक तकनीक से फसल और सौर ऊर्जा संयंत्र में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं होगी। एक ही भूमि पर नीचे फसलें उगाई जा सकती हैं और उसके ऊपर स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले वर्ष 55.29 गीगावाट गैर–जीवाश्म ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जो नॉर्वे की 40.6 गीगावाट, स्विट्जरलैंड की करीब 30 गीगावाट, ऑस्ट्रिया की 34 गीगावाट और बेल्जियम की करीब 33 गीगावाट कुल स्थापित बिजली क्षमता से अधिक है।

केरल के सीएम सतीशन ने एक्शन प्लान तैयार किया

तिरुवनंतपुरम, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने कहा कि केरल सरकार बजट में घोषित विकास परियोजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए एक नया सिस्टम बना रही है और साथ ही वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों पर आधारित राज्य–स्तरीय डेटाबेस भी तैयार कर रही है। साप्ताहिक कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद पत्रकारों से बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने यह पक्का करने के लिए एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम बनाने का फैसला किया है कि बजट प्रोजेक्ट्स को सही ढंग से और तय समय सीमा के अंदर लागू किया जाए। उन्होंने कहा, ष्इस पहल के तहत, 16 से 18 सितंबर तक तिरुवनंतपुरम में तीन दिन की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। प्रोजेक्ट प्लान, लागू करने के तरीकों और समय–सीमा को पक्का करने के लिए अलग–अलग ग्रुप्स में चर्चा की जाएगी। सतीशन ने कहा कि राज्य में यह पहली बार है जब बजट प्रस्तावों को जमीनी स्तर पर प्रोजेक्ट्स में बदलने के लिए इतना व्यापक एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, ष्40 से ज्यादा विभागों में घोषित 73 प्रोजेक्ट्स में से 63 के लिए दो या उससे ज्यादा विभागों के मिलकर काम करने की जरूरत है। सिर्फ 10 प्रोजेक्ट्स ही एक विभाग के अंतर्गत आते हैं। इस सिस्टम का मकसद विभागों के बीच खराब तालमेल से होने वाली देरी को रोकना है। छह ग्रुप्स में बांटे गए 34 चुने हुए प्रोजेक्ट्स के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स तैयार की जाएंगी। कॉन्फ्रेंस में प्रोजेक्ट्स के दायरे और उद्देश्यों, उन्हें लागू करने के तरीकों, आर्थिक मॉडलों और पूरा करने की खास समय–सीमा को अंतिम रूप दिया जाएगा। चर्चा में थिंक टैंक, पॉलिसी एक्सपर्ट्स, एकेडमिक और रिसर्च संस्थान, टेक्नोलॉजी संस्थान, अंतरराष्ट्रीय विकास पार्टनर, वित्तीय संस्थान, निवेशक, इंडस्ट्री एसोसिएशन और स्टार्टअप्स हिस्सा लेंगे। इन्हें लागू करने के लिए नियम और शर्तें पहले ही तय कर ली गई हैं।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने श्रीरामपुर में ममता बनर्जी की बैठक को सशर्त मंजूरी दी

कोलकाता, (एजेंसी)। कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल–जज बेंच ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शुक्रवार को हुगली जिले के श्रीरामपुर में होने वाले एक राजनीतिक कार्यक्रम को सशर्त मंजूरी दे दी। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट ने शुक्रवार को श्रीरामपुर में एक राजनीतिक कार्यक्रम की योजना बनाई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मुख्य वक्ता होंगी। गुट पहले श्रीरामपुर में एक जनसभा और उसके बाद एक रैली आयोजित करना चाहता था। जब पुलिस ने कार्यक्रम के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया, तो तृणमूल कांग्रेस गुट ने इसके लिए अनुमति मांगने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया।यह मामला गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल–न्यायाधीश पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया, और सुनवाई के अंत में, न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने श्रीरामपुर में रैली आयोजित करने के लिए सशर्त मंजूरी दे दी। हालांकि, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को वहां जनसभा करने की अनुमति देने के बावजूद, न्यायमूर्ति भट्टाचार्य की पीठ ने रैली के लिए अनुमति नहीं दी। अदालत ने पुलिस की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि यदि महेश से श्रीरामपुर कोर्ट तक प्रस्तावित रैली की अनुमति दी जाती है, तो व्यस्त ग्रैंड ट्रंक रोड पर भारी ट्रैफिक जाम हो जाएगा। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने श्रीरामपुर में ममता बनर्जी की ओर से संबोधित की जाने वाली जनसभा पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। अदालत ने बैठक के लिए समय सीमा दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक तय की है।

अगले वर्ष मार्च तक भ्रष्टाचार निवारण संगठन को मिल सकता है अपना अत्याधुनिक कार्यालय

चार करोड़ की लागत से मुगलपुरा–धारा रोड टीला पर बन रहा भवन

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।भ्रष्टाचार निवारण संगठन मंडल अयोध्या को अगले वर्ष मार्च तक अपना स्थायी और अत्याधुनिक कार्यालय मिलने जा रहा है।मुगलपुरा–धारा रोड टीला क्षेत्र पर एक एकड़ भूमि पर लगभग चार करोड़ रुपये की लागत से नए कार्यालय भवन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।विभागीय कर्मचारियों के मुताबिक निर्माण कार्य करीब दो माह पहले शुरू हुआ है और इसे मार्च 2027 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। बताया कि नए कार्यालय परिसर में सिर्फ अधिकारियों और कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था ही नहीं होगी, बल्कि बैठक कक्ष, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवास, वाहनों को खड़ा करने के लिए गैराज, मेस समेत अन्य आवश्यक और आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।इससे भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच और कार्रवाई के लिए आने वाले लोगों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।बताते चले कि वर्तमान में भ्रष्टाचार निवारण संगठन मंडल अयोध्या का कार्यालय पुलिस लाइन परिसर में सहायक रेडियो कार्यालय के बगल में संचालित हो रहा है।पिछले कई वर्षों से संचालित यहाँ अधिकारियों और कर्मचारियों के बैठने के साथ ही आवास तथा वाहनों को खड़ा करने के लिए पर्याप्त स्थान की समस्या बनी हुई है।इसी को देखते हुए विभाग की ओर से लंबे समय से नए कार्यालय के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश की जा रही थी।उच्च अधिकारियों के प्रयासों के बाद अब मुगलपुरा–धारा रोड टीला पर भूमि उपलब्ध होने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो गया है।बताया कि करीब चार करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहे इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है।परियोजना की निर्धारित अवधि करीब छह माह रखी गई है।बताया कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भ्रष्टाचार निवारण संगठन को एक ऐसा परिसर मिलेगा,जहां कार्यालय मे कार्यों के साथ अधिकारी व कर्मियों के आवास और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी।

संपादकीय

नीति में उचित बदलाव लाए

पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने की नीति के गंभीर परिणाम सामने होने के बावजूद सरकार में इस नीति पर पुनर्विचार के संकेत नहीं हैं। जबकि उचित यह होगा कि वह इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाए। केंद्र के इस दावे पर यकीन करना कठिन है कि चीनी आयात के फैसले का पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट से कोई संबंध नहीं है। अभी हाल तक अच्छी फसल वाले साल में भारत 70 लाख टन तक चीनी का निर्यात करता था। अब दस लाख टन चीनी आयात करने की नौबत आई है। गणित सीधा है। खबरों के मुताबिक 28 फीसदी इथेनॉल का उत्पादन गन्ने से हो रहा है। अनुमान है कि जितना गन्ना इसमें लगा, उससे 30 लाख टन चीनी बन सकती थी। ऐसा होता, तो देश में मांग की तुलना लगभग 20 लाख टन अतिरिक्त चीनी उपलब्ध रहती। इसलिए इस धारणा में दम है कि वाहनों में ईंधन के रूप इथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की गुमराह नीति विदेशी मुद्रा की किल्लत के दौर में चीनी जैसी सामान्य वस्तु के आयात के लिए जिम्मेदार है। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। चावल जैसे आम अनाज का भी इथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल बढ़ रहा है। खबरों के मुताबिक बीते अप्रैल–जुलाई के बीच भारतीय खाद्य निगम ने इस मकसद से 23.42 लाख टन चावल बेचा। वित्त वर्ष 2025–26 में इससे दो गुना चावल इसके लिए बेचा गया था। इस रुझान में किस तेजी से वृद्धि हुई है, इसे जानने के लिए इस पर गौर करना पर्याप्त होगा कि 2023–24 तक महज 8.96 लाख टन चावल का इथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल हुआ था। इस उद्देश्य के लिए मक्के का उपयोग भी बढ़ा है। संभवतरू ऐसी ही सूचनाओं से चिंतित होकर कुछ रोज पहले नरेंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागश्वेरन ने एक अखबार में लेख लिख कर अपनी चिंता जताई थी। उन्होंने इथेनॉल उत्पादन में बड़े पैमाने पर पानी के इस्तेमाल को लेकर भी आगाह किया था। तब तक चीनी आयात का फैसला सामने नहीं आया था। अब चूंकि इथेनॉल का यह परिणाम सामने है, तो बाकी चिंताएं भी अधिक गंभीर हो गई हैं। मगर सरकार के अंदर पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने की नीति पर पुनर्विचार के संकेत नहीं हैं। जबकि उचित यह होगा कि बिना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए वह तुरंत इस नीति में उचित बदलाव लाए।

विकास के आंकड़ों की जांच-परख

अभिषेक आनंद, जोश फेल्मन और अरविंद सुब्रमण्यन ने यह पूछा है कि जिस तिमाही में ऊर्जा के क्षेत्र में जोरदार झटके लगे हों, उसमें भारत की विकास दर आखिर 7.8 प्रतिशत कैसे हो सकती है। बेशक, यह एक उचित सवाल है। इसका एक जवाब भी है और वह जवाब पिछले कुछ वर्षों से सबके सामने ही है। समय से ही शुरुआत करते हैं। इस तिमाही की अवधि 1 अप्रैल से जून 2026 तक थी। इससे ठीक पहले ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं इजराइल के बीच का संघर्ष चरम पर पहुंच गया था। तेल की कीमतों में जोरदार उछाल आया और भारत ने इसका असर महसूस किया। हालांकि मार्च और अप्रैल के शुरुआती दिनों में इस जबरदस्त व्यवधान में कमी आई। मई आते–आते दबाव के बदल छंट गए। जून तक, मुश्किल दौर बीत चुका था। तीन महीने वाली तिमाही की शुरुआत के कुछ मुश्किल हफ्ते उस तिमाही के आंकड़ों को मनगढ़ंत नहीं बना देते। उन महीनों के सबूत एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं। ऑटोमोबाइल की बिक्री में निरंतर बढ़ोतरी हुई। एक प्रतिस्पर्धी मुद्रा की मदद से बैंक ऋण और निर्यात में बढ़ोतरी हुई। जीएसटी की दरों में कटौती के बावजूद, इसका संग्रह मजबूत बना रहा और हाल ही समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में इसमें 8.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। 2025–26 तक के तीन वर्षों में, जीएसटी के सकल संग्रह में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि श्नॉमिनल जीडीपीच्य में 31.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये दोनों आंकड़े बिल्कुल अलग–अलग क्षेत्रों से आए हैं और दोनों ही लगभग एक–दूसरे से मेल खाते हैं। जीएसटी रिटर्न कंपनियां दाखिल करती हैं। ऋण संबंधी आंकड़े बैंकों से आते हैं। व्यापार के आंकड़े बंदरगाहों से आते हैं। इनमें से कोई भी आंकड़ा सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा तैयार नहीं किया जाता है। अर्थव्यवस्था आखिर टिकी क्यों रही? क्योंकि कई सुधारों को एक साथ अपनाया गया। वर्ष 2022–23 के बाद से केन्द्र सरकार का पूंजीगत व्यय 65 प्रतिशत बढ़ा है और इस वर्ष इसमें 11.5 प्रतिशत और बढ़ोतरी का बजट रखा गया है। एक दशक में बनाई गई सड़कें, बंदरगाहें और बिजली संयंत्र तेल के महंगे होने पर ठप्प नहीं पड़े। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे ने अनौपचारिक गतिविधियों के एक बड़े हिस्से को औपचारिक बनाया और उन्हें मापी जा सकने वाली अर्थव्यवस्था में शामिल किया है। दिवाला संहिता ने डूबे हुए कर्ज (बैड डेट) से निपटने के बैंकों और कंपनियों के तौर–तरीकों को बदल दिया। रियल एस्टेट कानून ने उस सेक्टर को साफ–सुथरा बनाया, जो कभी अटकी हुई परियोजनाओं और पैसे के अपारदर्शी लेन–देन के लिए जाना जाता था। श्द इकोनॉमिस्ट्यि ने 2023 में उस सफाई अभियान का उल्लेख किया था। उसने नई दिल्ली पर कोई मेहरबानी नहीं की थी। इसके बाद, तेल की कीमतों में अचानक आए उछाल से निपटने के लिए सरकार ने जो कुछ किया, वह भी सामने है। उसने कीमतों में हुई बढ़ोतरी का बोझ आम परिवारों और कंपनियों पर नहीं डाला। उसने इसकी लागत खुद वहन की। राजकोषीय गुंजाइश (फिस्कल स्पेस) का उद्देश्य ही यही है और भारत ने इसे तैयार किया है। इसका सबूत 2 सितंबर को मिला। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग को बीबीबी से बढ़ाकर ए– कर दिया और इसके साथ ही स्थिर संभावना भी जताई। इसके अलावा, देश की रेटिंग सीमा (कंट्री सीलिंग) को भी ए कर दिया। भारत को तीन दशकों से अधिक समय से श्च्य रेटिंग नहीं मिली है। एजेंसी ने डिजिटल सार्वजनिक ढांचे, जीएसटी, दिवाला संहिता और सकल गैर–निष्पादित ऋण अनुपात (ग्रॉस नॉन–परफॉर्मिंग लोन रेश्यो) के 1.8 प्रतिशत तक कम होने का उल्लेख किया। उसने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार ने उच्च पूंजीगत व्यय को जारी रखते हुए भी अपने राजकोषीय घाटे को वित्तीय वर्ष 2025 में जीडीपी के 4. 7 प्रतिशत से घटाकर वित्तीय 2026 में 4.4 प्रतिशत कर लिया। टोक्यो स्थित एक रेटिंग समिति के लिए दिल्ली में किसी को खुश करने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने भी उन्हीं सुधारों को देखा और वही नतीजा निकाला। अब आलोचना के मुख्य बिंदु पर आते हैं। लेखकगण पूछते हैं कि अगर आज ये संकेतक 7.8 प्रतिशत की विकास दर को सही ठहराते हैं, तो पूर्व के वर्षों में वैसी ही विकास दर कमजोर संकेतकों के साथ क्यों संभव हुई थी? यह मान लेना कि विकास हमेशा एक जैसी चीजों से ही संभव होती है, जरूरी नहीं है। निर्यात और औपचारिक ऋण से प्रेरित तिमाही, घरेलू खर्च या सरकारी निवेश से चलने वाले वर्ष जैसी नहीं होगी। पूर्व के वर्षों में विकास के अपने कारण थे, जो उस समय साफ दिख रहे थे। वर्ष 2024–25 तक, शेयर बाजार तेजी से चढ़ा और अधिक संख्या में भारतीयों ने निवेश करना शुरू किया। वर्ष 2022–23 और 2024–25 के बीच परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत में 60 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई। गैर–बैंक और तकनीक–आधारित ऋणदाता तेजी से बढ़े। वाणिज्यिक क्षेत्र में कुल संसाधनों का प्रवाह तीन वर्षों में 72 प्रतिशत बढ़ा, जिसमें गैर–बैंकों की हिस्सेदारी 96 प्रतिशत बढ़ी।

ब्रिक्स 2026- भारत की कूटनीतिक क्षमताओं को चुनौती देता

गोपल

2026 में ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स के मौजूदा माहौल के आधार पर, ब्रिक्स एक इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के शॉर्ट फॉर्म से बढ़कर एक बड़ी इंस्टीट्यूशनल ताकत बन गया है जो उभरते हुए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को आकार दे रहा है। इसके महत्व, उपलब्धियों, चुनौतियों और ब्रिक्स विरोधी बातों को सुलझाने के प्रयासों को समझना आवश्यक है। ब्रिक्स ग्लोबल साउथ के हितों को बताने और एक ज़्यादा संतुलित बहुध्रुवीय विश्व बनाने के लिए एक बुनियादी प्लेटफॉर्म बन गया है। 2025 तक, ब्रिक्स के सदस्य देश दुनिया की लगभग 48: आबादी और परचेसिंग पावर पैरिटी (पी पी पी) के आधार पर ग्लोबल जीडीपी का 39: हिस्सा थे। भारत की 2026 ब्रिक्स प्रेसीडेंसी के तहत, इस की गाइडिंग थीम ष्बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटीष है। कमजोर ग्लोबल गवर्नेंस, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी और बढ़ती जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता के दौर में, ब्रिक्स साउथ–साउथ सहयोग के लिए एक सही विकल्प देता है जो पारंपरिक दबदबे और हुक्म से रहित है। यह उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को अपनी पार्टनरशिप में विविधता लाने और ग्लोबल गवर्नेंस में अपनी आवाज बुलंद करने की इजाजत देता है, बिना कोल्ड वॉर–स्टाइल के बाइनरी अलाइनमेंट में मजबूर हुए। ब्रिक्स ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इसका सफर आसान नहीं था। कई चुनौतियों के बावजूद यह अपने अनेक लक्ष्यों को हासिल कर सका। कुछ मुख्य उपलब्धियां हैं। ब्रिक्स ने सफलतापूर्वक अपनी पहुंच बढ़ाई है। 2026 तक, इस ब्लॉक में ऑफिशियली 11 सदस्य देश शामिल हैंरू ओरिजिनल पांच (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) प्लस मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब (हालांकि सऊदी अरब अपने फॉर्मल स्टेटस को लेकर कुछ डिप्लोमैटिक अस्पष्टता बनाए हुए है)। मुख्य फैसले लेने की क्षमता को कम किए बिना अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए, ब्रिक्स ने एक फॉर्मल ष्पार्टनर देशष कैटेगरी शुरू की। 2025 में, दस देशकृबेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनामकृऑफिशियल पार्टनर के तौर पर शामिल हुए, जिससे एंगेजमेंट के लिए एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क बना। न्यू डेवलपमेंट बैंक (एन डी बी) की उपलब्धियाँ एन डी बी ने हाल ही में अपनी 10वीं वर्षगाँठ मनाई, जिसमें क्लीन एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 120 से ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया गया। इसने ग्लोबल साउथ को पार्टनरशिप, सॉवरेनिटी और शेयर्ड प्रायोरिटीज पर बना एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक सफलतापूर्वक दिया है, न कि वेस्टर्न–लेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स से जुड़ी कंडीशनैलिटीज पर। इंट्रा–ब्रिक्स ट्रेड ग्रोथरू मेंबर्स के बीच दो दशकों के ट्रेड एक्सपेंशन ने डेवलप हो रहे इकोनॉमिक संबंधों को सामने लाया है, जिससे साउथ–साउथ ट्रेड के नए, रेसिलिएंट पैटर्न बने हैं जो बाहरी झटकों से कम वल्नरेबल हैं। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने 5 सितंबर, 2026 को कहा कि इंट्रा–ब्रिक्स मर्चेंडाइज ट्रेड अब कई गुना बढ़ गया है, जो मेंबर देशों के बीच गहरे ट्रेड इंटीग्रेशन और मजबूत इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा अनटैप्ड पोटेंशियल को हाईलाइट करता है। 2003 में +84 बिलियन से 2024 में +1.17 ट्रिलियन तक इंट्रा–ब्रिक्स मर्चेंडाइज ट्रेड 13 गुना बढ़ गया, जो 13.3 परसेंट की सालाना एवरेज रेट से बढ़ रहा है, जो इसी समय के दौरान 5.7 परसेंट की ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ से काफी ज़्यादा है। ब्रिक्स कनेक्ट्स को लागू करना। भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता की पहल ब्रिक्स कनेक्ट्स का उद्देश्य सदस्य देशों के नागरिकों को लाभ पहुँचाने को प्राथमिकता देना है। इसके मुख्य फोकस एरिया में डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल इनक्लूजन (वित्तीय समावेश) को बढ़ाना, एजुकेशनल डिग्री को आपसी मान्यता देना, सस्ता इंटरनेट और इंसानों पर केंद्रित ए आई, एक नया ब्रिक्स स्टार्टअप नॉलेज हब, और बेहतर ट्रेड कॉरिडोर शामिल हैं, जिनसे लॉजिस्टिक्स की लागत कम हो सकती है और सामान सस्ता हो सकता है। यह ग्रुप एक जैसा ग्रुप नहीं है, जिससे आम सहमति बनाना मुश्किल हो जाता है। इसमें बहुत अलग–अलग जियोपॉलिटिकल सोच वाले देश हैं, जिनमें वे देश शामिल हैं जो पश्चिम का सक्रिय रूप से सामना कर रहे हैं (जैसे, रूस, ईरान) से लेकर वे देश भी शामिल हैं जो पश्चिमी देशों (जैसे, भारत, ब्राजील) के साथ मजबूत स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक संबंध बनाए हुए हैं। ब्रिक्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वह खुद को ज़्यादा बढ़ाए बिना अपनी बढ़ती जियोपॉलिटिकल अहमियत को ठोस इंस्टीट्यूशनल असर में बदले। तेजी से विस्तार से इस ग्रुप के बेकाबू होने और निर्णायक रूप से काम करने की इसकी क्षमता कम होने का खतरा है। फाइनेंशियल इंटीग्रेशन पर सदस्यों के अलग–अलग विचार हैं। जहां कुछ लोग वेस्ट से तेजी से फाइनेंशियल डीकपलिंग पर जोर देते हैं, वहीं दूसरे प्रैक्टिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हैं और बड़े फाइनेंशियल बदलावों के नतीजों से डरते हैं। ब्रिक्स उस पश्चिमी नैरेटिव को बेअसर करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है जिसके तहत इसे ष्पश्चिम–विरोधी क्लबष या एक विघटनकारी ताकत के तौर पर देखा जाता है। इन कोशिशों से निपटने के लिए यह कई रणनीतियाँ अपनाता है 2026 में भारत की अध्यक्षता में नेतृत्व ने टकराव वाली छवि को स्पष्ट रूप से खारिज किया है। आधिकारिक राजनयिक रुख इस बात पर जोर देता है कि ष्ब्रिक्स पश्चिम–विरोधी नहीं हैय यह संतुलन का पक्षधर है और ब्रिक्स देशों को ळ7–विरोधी नहीं बनना चाहिए, और ळ7 को ब्रिक्स –विरोधी नहीं बनना चाहिए।ष यह समूह खुद को स्वाभाविक रूप से विरोधी के बजाय गैर–पश्चिमी और सुधारवादी के तौर पर पेश करता है। गंभीर आर्थिक जवाबी कार्रवाई (जैसे टैरिफ की धमकियाँ) से बचने के लिए, ब्रिक्स ने डी–डॉलरलाइजेशन से जुड़ी अपनी बयानबाजी को नरम किया है। अमेरिकी डॉलर या ब्रिक्स की साझा मुद्रा को अचानक और पूरी तरह से बदलने के बजायकृजिसका भारत जैसे सदस्यों ने स्पष्ट रूप से विरोध किया है।

सत्य निकेतन हादसा– जिम्मेदार अधिकारियों पर हो ठोस कार्रवाई

ललित

दिल्ली के सत्य निकेतन में रविवार को पांच मंजिला छात्र–पीजी भवन का भरभराकर गिर जाना केवल एक दर्दनाक हादसा नहीं है। यह उस व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न है, जो भवन बनने देती है, उसमें अनधिकृत निर्माण होने देती है, उसमें विद्यार्थियों को रहने देती है, उसकी कमजोरियों को वर्षों तक नजरअंदाज करती है और फिर उसके ढह जाने के बाद जागती है। इस हादसे में अब तक छह लोगों की मौत की सूचना है और कई लोग घायल हुए हैं। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार भवन में बेसमेंट और कई ऊपरी मंजिलों में मरम्मत या निर्माण संबंधी काम चल रहा था। प्रशासन ने मजिस्ट्रेट जांच और भवन मालिक के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि हादसे के बाद किसके खिलाफ एफआईआर होगी? असली सवाल यह है कि हादसे से पहले जिम्मेदार अधिकारी कहां थे? यदि निर्माण नियमों का उल्लंघन था, यदि भवन का स्वीकृत नक्शा नहीं था, यदि अतिरिक्त मंजिलें बनाई गई थीं, यदि बेसमेंट में निर्माण चल रहा था, यदि भवन छात्रों के रहने के लिए इस्तेमाल हो रहा था और यदि वह संरचनात्मक रूप से जोखिमपूर्ण था, तो इन सबका पता प्रशासन को तब क्यों नहीं चला जब वहां निर्माण हो रहा था? सत्य निकेतन दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर के आसपास विद्यार्थियों का प्रमुख इलाका है। देश के विभिन्न राज्यों से हजारों युवा यहां अपने भविष्य के सपने लेकर आते हैं। वे छोटे–छोटे कमरों, पीजी और किराये के मकानों में रहकर पढ़ते हैं। उनके माता–पिता अपनी जीवनभर की कमाई का बड़ा हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर लगाते हैं और यह विश्वास करते हैं कि राजधानी में उनका बच्चा सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब शिक्षा की तलाश में निकला युवा एक ऐसी इमारत में पहुंचता है, जिसकी नींव ही नियमों और सुरक्षा के साथ समझौते पर टिकी हो, तो विकास की हमारी पूरी अवधारणा कटघरे में खड़ी हो जाती है और यह कोई पहली चेतावनी नहीं है। 2022 में भी सत्य निकेतन में निर्माणाधीन चार मंजिला इमारत ढहने से दो मजदूरों की मौत हुई थी और चार लोग घायल हुए थे। उस समय भी निर्माण कार्य, सुरक्षा और भवन की निगरानी पर सवाल उठे थे। लगभग चार साल बाद उसी इलाके में फिर एक बड़ी इमारत ढह गई। इसका अर्थ है कि हमने घटना से सबक लेने के बजाय घटना को एक समाचार की तरह देखा और आगे बढ़ गए। यहां भ्रष्टाचार की बात करते समय एक सावधानी भी जरूरी है। किसी अधिकारी या व्यवसायी को बिना जांच दोषी ठहराना उचित नहीं। लेकिन यदि जांच में यह सिद्ध होता है कि नियमों के विरुद्ध निर्माण को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया, निरीक्षण में लापरवाही हुई या किसी प्रकार की मिलीभगत रही, तो जिम्मेदारी केवल भवन मालिक तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जिसने नियम तोड़े और जिसने नियम तोड़ने दिए–दोनों को जवाबदेह बनाना होगा। सत्य निकेतन की त्रासदी को जुलाई 2024 के पुराने राजेंद्र नगर हादसे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। वहां राव आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में पानी भर जाने से तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों–तनीया सोनी, श्रेया यादव और नवीन डालविन की मृत्यु हुई थी। सबसे भयावह तथ्य यह था कि बेसमेंट का उपयोग लाइब्रेरी के रूप में हो रहा था, जबकि उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार उसे पार्किंग और स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इससे भी अधिक चिंताजनक बात सामने आई–हादसे से लगभग एक महीने पहले एक विद्यार्थी ने एमसीडी में शिकायत की थी। भारत में भवन निर्माण के लिए नियमों की कमी नहीं है। नक्शा स्वीकृति, भवन उपविधियां, अग्नि सुरक्षा, संरचनात्मक सुरक्षा, अधिभोग प्रमाणपत्र, पार्किंग, बेसमेंट के उपयोग–हर क्षेत्र के लिए नियम हैं। लेकिन समस्या नियमों की संख्या नहीं, उनके पालन की ईमानदारी है। जब किसी भवन में एक मंजिल की अनुमति हो और चार–पांच मंजिलें खड़ी हो जाएं, जब बेसमेंट स्टोरेज के लिए स्वीकृत हो और वहां लाइब्रेरी या व्यावसायिक गतिविधि चलने लगे, जब सड़क की जलनिकासी बाधित हो और फिर भी निर्माण चलता रहे–तो सवाल केवल नागरिक की मनमानी का नहीं है। सवाल उस पूरी निगरानी व्यवस्था का है, जो आंखों के सामने होने वाले बदलाव को देखने के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं करती। भ्रष्टाचार केवल रिश्वत लेने का नाम नहीं है। भ्रष्टाचार वह भी है जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति अपने कर्तव्य को जानबूझकर न निभाए। किसी अवैध निर्माण को देखकर आंखें बंद कर लेना भी व्यवस्था के प्रति अपराध है। किसी भवन को जोखिमपूर्ण जानते हुए कार्रवाई न करना भी भ्रष्ट प्रशासनिक संस्कृति का हिस्सा है। सरकारी भवन भी सुरक्षित नहीं तो आम आदमी किस पर भरोसा करे? मई 2024 में दिल्ली के आईटीओ स्थित सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग में आग लगी थी। 46 वर्षीय ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की धुएं में दम घुटने से मृत्यु हुई थी। रिपोर्टों के अनुसार भवन पुराना था और उसमें आधुनिक फायर–स्प्रिंकलर व्यवस्था भी नहीं थी। यह घटना एक और सवाल सामने रखती है–जब सरकारी भवनों में भी सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, तो निजी और अनधिकृत भवनों की निगरानी की स्थिति क्या होगी? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और देश के अन्य महानगरों में अनियोजित शहरी विस्तार लगातार बढ़ रहा है। जमीन सीमित है, जनसंख्या बढ़ रही है, किराये की मांग बढ़ रही है और व्यावसायिक हित अधिकतम जगह का अधिकतम उपयोग चाहते हैं। ऐसे में यदि शासन मजबूत नियमन और वैज्ञानिक शहरी नियोजन नहीं करेगा तो शहर ऊपर की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उनकी सुरक्षा नीचे गिरती जाएगी। दुर्घटना के बाद वही परिचित दृश्य सामने आता है–मंत्री घटनास्थल पर पहुंचते हैं, अधिकारी बैठक करते हैं, मुआवजे की घोषणा होती है, जांच समिति बनती है, कुछ भवन सील होते हैं, कुछ गिरफ्तारियां होती हैं और कुछ दिनों तक प्रशासन सक्रिय दिखाई देता है। फिर धीरे–धीरे सब सामान्य हो जाता है। लेकिन किसी मृत विद्यार्थी के माता–पिता के लिए कुछ भी सामान्य नहीं होता। उनके लिए वह एक जांच समिति नहीं, जीवनभर का खालीपन है। उनके लिए मुआवजे की राशि उनके बेटे या बेटी का विकल्प नहीं है। वे यह जानना चाहते हैं कि उनका बच्चा सुरक्षित क्यों नहीं था? किसने सुरक्षा की गारंटी दी थी? किसने निगरानी की थी? किसने खतरे को नजरअंदाज किया था? इसलिए जांच का उद्देश्य केवल दोषी व्यक्ति ढूंढना नहीं होना चाहिए। जांच को यह भी पता लगाना चाहिए कि किस स्तर पर सिस्टम विफल हुआ। फाइल कहां रुकी? निरीक्षण किसने किया? शिकायत किसने दबाई? नक्शा किस आधार पर स्वीकार हुआ? अवैध निर्माण वर्षों तक कैसे चलता रहा? भवन में रहने वालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? और सबसे महत्वपूर्ण–क्या उन अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी जिनकी जिम्मेदारी ही ऐसे हादसों को रोकना थी?

कॉकरोच से लगे झटके के बाद अपनी छवि सुधारने की तैयारी में मोदी

कल्याणी शंकर

नेटवर्क जुड़ें आने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन मोदी को भारत और अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि को बेहतर बनाने का एक खास मौका देता है। सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, जो भारत के बढ़ते प्रभाव और आर्थिक क्षमता को दिखाते हैं। मौजूदा आर्थिक संकट के कारण मोदी आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने और जनता का भरोसा बहाल करने के लिए कदम उठा रहे हैं। खबरों के अनुसार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और विदेश की कई चुनौतियों के बीच अपनी जनछवि को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। भारत जैसे विविध और बड़ी आबादी वाले देश के नेता के तौर पर, मोदी लोगों का मजबूत समर्थन बनाए रखने की अहमियत समझते हैं। जिन लोगों की वे सेवा करते हैं, उनकी बात सुनना भरोसा बढ़ाने और असरदार शासन सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है।श्इंडिया टुडेश और श्सीवोटर मूड ऑफ द नेशनश सर्वे के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि मोदी की लोकप्रियता घटकर 49 प्रतिशत हो गई है। इसके मुकाबले, विपक्ष के नेता राहुल गांधी की लोकप्रियता 27 प्रतिशत पर स्थिर बनी हुई है। चुनावी अनुमानों में, भाजपा के 24 लोकसभा सीटें हारने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस को 26 सीटें अधिक मिल सकती हैं। इससे पता चलता है कि आर्थिक मुद्दे वोटरों की चिंताओं में सबसे ऊपर हैं। सच तो यह है कि उनकी जगह कोई दूसरा नेता नहीं ले सकता। मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में हैं, और वोटरों की चिंताओं को दूर करने के लिए उन्हें अपनी सार्वजनिक छवि को नए सिरे से पेश करना जरूरी है। आर्थिक सुधार और नौकरियां पैदा करने पर जोर देने से उनके नेतृत्व में भरोसा फिर से कायम करने में मदद मिल सकती है। 2014 में पद संभालने के बाद से, मोदी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिन्होंने उनके नेतृत्व के बारे में लोगों की राय और भरोसे को प्रभावित किया है। हालांकि इतने सालों में उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता काफी हद तक बनी रही है, लेकिन 2024 में उन्हें एक झटका लगा जब वे चुनावों में बहुमत हासिल नहीं कर पाए।2029 के चुनाव में वे चौथी बार अपनी पार्टी का नेतृत्व करेंगे। फिर भी, उनके नेतृत्व की जांच–परख हो रही है, खासकर आर्थिक मंदी, बढ़ती बेरोजगारी और कोविड–19 महामारी के बुरे असर जैसी बड़ी मुश्किलों के बीच। इन घटनाओं ने विपक्षी दलों, आर्थिक विशेषज्ञों और आम जनता की आलोचना को जन्म दिया है, जिससे उन नागरिकों में नाराजगी बढ़ी है जिनकी नौकरियां चली गईं और महामारी के लॉक डाउन के दौरान जिनके कारोबार बंद हो गए। हाल ही में, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सामने आने से वह और उनकी सरकार के लोग हैरान हैं।बुकर प्राइज विजेता लेखिका अरुंधति रॉय ने कहा है, श्पीएम मोदी की छवि, जिसे करोड़ों रुपये खर्च करके 24 सालों में बनाया गया था, उसे सीजेपी ने दो हफ्तों में ही बर्बाद कर दिया।श इ मोदी के मुख्य लक्ष्यों में से एक है वैश्विक मंच पर अपनी छवि को बेहतर बनाना, खासकर तब जब भारत अंतरराष्ट्रीय मामलों में अहम भूमिका निभा रहा है। घरेलू मुद्दों के अलावा, मोदी जी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कुशलता से काम करना होगा। जैसे–जैसे भारत वैश्विक मंच पर आगे बढ़ रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि का असर राजनयिक संबंधों और विदेशी निवेश पर पड़ेगा।अपनी और भारत की छवि को बेहतर बनाने के लिए काम करके, मोदी एक ऐसे नेतृत्व तौर–तरीके पर जोर दे सकते हैं जो समझदार और लोगों से जुड़ा हुआ हो, जिससे वैश्विक राजनीति में भारत की अहमियत बढ़े। अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ जुड़ने और जरूरी वैश्विक चुनौतियों का सामना करने से कई मोर्चों पर एक काबिल नेता के तौर पर उनकी प्रतिष्ठा मजबूत हो सकती है। आने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन मोदी को भारत और अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि को बेहतर बनाने का एक खास मौका देता है। सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, जो भारत के बढ़ते प्रभाव और आर्थिक क्षमता को दिखाते हैं। मौजूदा आर्थिक संकट के कारण मोदी आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने और जनता का भरोसा बहाल करने के लिए कदम उठा रहे हैं। इन चुनौतियों का डटकर सामना करने के अपने संकल्प को दिखाकर, मोदी वोटरों को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि वे देश के भविष्य पर असर डालने वाले मुद्दों को हल करने के लिए कड़े फैसले लेने को तैयार हैं। मोदी के नेतृत्व के तौर–तरीके में मजबूत राष्ट्रवाद और फैसले लेने की क्षमता दिखती है, जिससे उन्हें वफादार समर्थक मिले हैं। हालांकि, अपनी अपील को व्यापक बनाने के लिए, उन्हें एक ऐसी छवि पेश करने की जरूरत हो सकती है जो एकता और विविधता पर जोर दे। क्योंकि राज्य के चुनाव राजनीतिक योजना और रणनीति से तय होते हैं, इसलिए ये बातें ज़्यादा मायने रखती हैं। मोदी अवसंरचनात्मक विकास, डिजिटल बदलाव, कल्याणकारी कार्यक्रमों और स्वास्थ्य देखभाल, और शिक्षा में सुधार के मामले में अपनी सरकार की उपलब्धियों को उजागर कर सकते हैं। इन

सफलताओं को दिखाने से एक नेता के तौर पर उनकी काबिलियत साबित हो सकती है और उनकी सार्वजनिक छवि मजबूत हो सकती है। इन लक्ष्यों को पाने के लिए, मोदी कई तरह की संवाद और संचार रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें सोशल मीडिया, सार्वजनिक भाषण और स्थानीय मुद्दों से सीधे जुड़ना शामिल है। उनके भाषण देने के अंदाज और जनता से सीधे जुड़ने के तरीके के अच्छे नतीजे मिले हैं। उनके संदेशों में अक्सर सहानुभूति, तत्परता और जवाबदेही पर जोर दिया जाता हैकृये ऐसे गुण हैं जो वोटरों, खासकर जो मुश्किल समय में हैं, पर गहरा असर डालते हैं।निष्कर्ष के तौर पर, अपनी सार्वजनिक छवि को बेहतर बनाने के मोदी के प्रयास आंतरिक चुनौतियों और बाहरी धारणाओं से निपटने की एक बहुआयामी रणनीति को दर्शाते हैं। जनभावना, आर्थिक हकीकत और वैश्विक स्थितियों को कुशलता से संभालकर, वह अपने नेतृत्व को मजबूत करना और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लगातार बदलते राजनीतिक माहौल में प्रासंगिक बने रहने और समर्थन बनाए रखने के लिए किसी भी नेता के लिए यह व्यापक दृष्टिकोण जरूरी है, खासकर तब जब वह भविष्य की चुनावी चुनौतियों की तैयारी कर रहा हो। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई दूसरा नेता ऐसा नजर नहीं आता जो उनकी लोकप्रियता से कहीं आगे हो। अपनी छवि को फिर से बनाने की मोदी की कोशिशें, अंदरूनी चुनौतियों और बाहरी धारणाओं, दोनों से निपटने की एक बहुआयामी रणनीति को दिखाती हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों में, भाजपा का मकसद राज्य पर अपना कब्जा बनाए रखना होगा।

किसानों ने डीएम को सौंपा पत्र, पीएमओ घेराव की चेतावनी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग–233 के निर्माण और भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर लंबित मुआवजा ब्याज समेत दिलाने और अधूरे व जर्जर मार्ग पर टोल वसूली बंद कराने की मांग की। पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष अजीत सिंह के नेतृत्व में पहुंचे किसानों ने चेतावनी दी कि 20 सितंबर तक मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो 30 सितंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय वाराणसी और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के रीजनल कार्यालय के घेराव व विरोध–प्रदर्शन किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अध्यक्ष अजीत सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग–233 (वाराणसी–आजमगढ़ मार्ग) के निर्माण एवं भूमि अधिग्रहण से केराकत तहसील के करीब चार हजार किसान पिछले 14 वर्षों से मुआवजे और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके अनुसार एनएचएआई द्वारा करीब 150 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया जा चुका है, लेकिन कई किसानों को अभी तक पूरा मुआवजा नहीं मिला है और वर्ष 2012 से देय ब्याज का भी भुगतान लंबित है। किसानों का आरोप है कि मार्ग का निर्माण पूरा नहीं होने के बावजूद पुरानी, संकरी और जर्जर सड़क पर टोल वसूली शुरू कर दी गई है। इससे भारी वाहनों के आवागमन के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने ढेरही टोल प्लाजा की वसूली तत्काल बंद कराने तथा अधूरे मार्ग पर सुरक्षा और आवश्यक नो–एंट्री व्यवस्था लागू करने की मांग की। किसानों ने लंबित निर्माण कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा कराने और सड़क दुर्घटनाओं में मृत लोगों के परिवारों को कम से कम एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि करीब दो वर्ष पूर्व जिला प्रशासन, एनएचएआई अधिकारियों और किसानों के बीच हुई बैठकों में टोल वसूली बंद करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बाद में इसे फिर शुरू कर दिया गया। किसानों ने कहा कि 20 सितंबर तक सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा।

पीजीआई के डॉक्टरों ने 45 मिनट में किया कमाल, दुर्लभ सर्जरी कर बचाई जान

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ स्थित पीजीआई के एपेक्स ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टरों ने दुर्लभ और बेहद चुनौतीपूर्ण सर्जरी कर 53 वर्षीय मरीज के सीने से 11 साल से फंसा बरमा (ड्रिल बिट) बाहर निकाला है। मरीज लंबे समय से सीने में असहनीय दर्द से पीड़ित था। एपेक्स ट्रॉमा सेंटर के डॉ. अमित कुमार सिंह ने बताया कि कुशीनगर निवासी अब्दुल कादिर तीन दिन पहले एपेक्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचे थे। उनका दाहिना हाथ काफी मुड़ा हुआ था, जिससे वह सामान्य काम तक नहीं कर पा रहे थे। हाथ में टेढ़ापन और पस निकलने के साथ सीने में दर्द की शिकायत भी थी। डॉक्टरों ने सीटी स्कैन कराया तो सीने के भीतर धंसा हुआ बरमा दिखाई दिया। डॉक्टरों ने 45 मिनट के जटिल ऑपरेशन के दौरान न सिर्फ सीने से बरमा निकाला, बल्कि एक ही सर्जरी में मरीज के हाथ की हड्डी की पुरानी समस्या का भी स्थायी उपचार कर दिया। ऑपरेशन के बाद मरीज को दर्द से पूरी तरह राहत मिल गई है और वह तेजी से रिकवर हो रहा है। अब्दुल कादिर वर्ष 2014 में सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे। हादसे में उनकी दाहिनी बांह की ह्यूमरस हड्डी (कंधे से कोहनी तक की हड्डी) टूट गई थी। वर्ष 2015 में वह लोहिया संस्थान पहुंचे, जहां हड्डी को जोड़ने के लिए बांह में धातु की प्लेट और स्क्रू लगाए गए। वर्ष 2018 में जमीन पर गिरने के बाद हाथ में दोबारा दर्द और विकृति हो गई। इसके बाद प्लेट हटाकर नेलिंग (हड्डी के अंदर धातु की एक मजबूत रॉड या कील डालना) की गई। वर्ष 2023 में फिर गिरने से हाथ में दर्द और टेढ़ापन आ गया।

संक्षिप्त खबरें

भारतीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों के निर्माण और ज्ञान–सृजन को बढ़ावा देने पर जोर

लखनऊ, (संवाददाता)। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में बीबीएयू एवं भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में 'भारतीय भाषा पुस्तक योजना के राज्य स्तरीय क्रियान्वयन हेतु' विषय पर आयोजित द्विदिवसीय कार्यशाला का मंगलवार को समापन हुआ। कार्यक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल के दिशानिर्देशन एवं संरक्षण में आयोजित किया गया। कार्यशाला के दौरान भारतीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों के लेखन, प्रकाशन और प्रसार को बढ़ावा देने, भारतीय ज्ञान परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने तथा शिक्षा और शोध में भारतीय भाषाओं के प्रभावी उपयोग पर व्यापक विचार–विमर्श हुआ।समापन सत्र में काशी विद्यापीठ, बनारस के प्रो. नरेंद्र नारायण, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर की प्रो. सुषमा पाण्डेय, भारतीय भाषा समिति के शैक्षणिक समन्वयक डॉ. चंदन श्रीवास्तव, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, बनारस के प्रो. शैलेश मिश्रा, जवाहर लाल नेहरू स्मारक पीजी कॉलेज, महाराजगंज के प्रधानाचार्य डॉ. अजय मिश्रा तथा कार्यक्रम संयोजक डॉ. बलजीत कुमार श्रीवास्तव उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रो. उदयन मिश्र ने सभी अतिथियों, शिक्षकों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए की। उन्होंने कार्यशाला के उद्देश्यों और रूपरेखा की जानकारी दी।काशी विद्यापीठ, बनारस के प्रो. नरेंद्र नारायण ने अपने संबोधन में भारतेन्दु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध पंक्तियों 'निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा–ज्ञान के, मिटत न हिय को सूलघ' का उल्लेख करते हुए ।

सेवा पखवाड़े में गांव–गांव पहुंचेगा जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ

लखनऊ, (संवाददाता)। केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचाने के उद्देश्य से आगामी 'सेवा पखवाड़ा' को व्यापक जनभागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सोमवार को राज्यों के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ उच्चस्तरीय वर्चुअल बैठक हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ स्थित कैम्प कार्यालय से वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।बैठक में सेवा पखवाड़े के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी एवं ग्रामीण विकास योजनाओं को पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन की गति बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं की अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करने, पात्र लोगों को समय से लाभ उपलब्ध कराने और गांवों में विकास कार्यों को गति देने पर विशेष जोर दिया गया।केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 'सेवा पखवाड़ा' सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प को धरातल पर उतारने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने राज्यों से आह्वान किया कि पखवाड़े के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।

पर्यावरण मंत्री सक्सेना बोले- गंगा हमारी आस्था का विषय, इसकी निर्मलता के लिए सबकी भागीदारी जरूरी

लखनऊ, (संवाददाता)। गंगा हमारे लिए सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि आस्था और जीवन से जुड़ी धरोहर है। देश में गंगा की पूजा से लेकर अंतिम समय में मुंह में गंगाजल डालने तक इसकी गहरी धार्मिक मान्यता है। हवा के बाद जीवन के लिए पानी सबसे जरूरी है। नदियां हमारे जीवन की धमनियों की तरह हैं, इसलिए नदियों का संरक्षण हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। यह बातें उत्तर प्रदेश के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री अरुण सक्सेना ने कही। वह मंगलवार को गोमतीनगर स्थित एक होटल में अमर उजाला के निर्मल गंगा–प्रदूषण मुक्त उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाने और जल, जमीन व हवा बचाने पर जोर दिया। कहा कि इस बार कुंभ से लौटने वालों में गंगा प्रदूषण से गैस्ट्रो संबंधी समस्याएं नहीं दिखीं। जनभागीदारी को गंगा की निर्मलता की सबसे बड़ी ताकत बताया। कार्यक्रम में एचडीएफसी बैंक की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोनिका गाखर, एसबीआई उत्तरप्रदेश सचिवालय के सहायक महाप्रबंधक आलोक श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में पर्यावरण कार्यकर्ता व सुधीजन मौजूद रहे। पहले सत्र में पद्मश्री उमाशंकर पांडेय ने जल संरक्षण को साझा जिम्मेदारी बताते हुए खेतों में मेड़, पेड़ लगाने और घरेलू इस्तेमाल हो रहे पानी को रीसाइकल करने पर जोर दिया। जल विश्वविद्यालय बनाने की मांग उठाई। जल निगम (ग्रामीण) के प्रबंध निदेशक योगेश कुमार ने सरकारी एजेंसियों में समन्वय पर जोर दिया।

लंबित अनुमोदन और भुगतान को लेकर एफपीओ संगठनों में आक्रोश

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार की "आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना" के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लगभग 500 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के अनुमोदन लंबित होने, सीबीबीओ एवं एफपीओ संस्थाओं के भुगतान में देरी तथा 30 सितंबर के बाद प्रस्तावित 200 रुपये प्रतिदिन की पेनाल्टी को लेकर किसान उत्पादक संगठनों में नाराजगी बढ़ गई है। संगठनों ने समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग करते हुए 9 सितंबर 2026 से कृषि भवन में धरना–प्रदर्शन शुरू करने का निर्णय लिया है। दावा किया गया है कि धरने में करीब 600 किसान शामिल होंगे।कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश के निदेशक को दिए गए पत्र में कहा गया है कि योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से संगठित कर उनकी आय बढ़ाना, कृषि आधारित उद्यमिता को प्रोत्साहित करना तथा किसानों को बेहतर बाजार और कृषि सेवाओं से जोड़ना है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के अंतर्गत लगभग 500 एफपीओ का पंजीकरण हो चुका है, लेकिन उनका अनुमोदन अभी तक लंबित है।पत्र में कहा गया है कि पंजीकरण के बाद एफपीओ ने अपने संचालन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और लेखाकार की नियुक्ति, कार्यालय की स्थापना, फर्नीचर व स्टेशनरी की व्यवस्था, किसान सदस्यों को जोड़ने के लिए बैठकों तथा क्षेत्रीय भ्रमण सहित विभिन्न प्रारंभिक गतिविधियों पर अपने स्तर से खर्च किया है। अनुमोदन लंबित रहने के कारण इन संगठनों को गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।संगठनों का कहना है कि योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सीबीबीओ संस्थाओं के वैध भुगतान भी लंबे समय से लंबित हैं। संबंधित संस्थाओं द्वारा कार्यदायी संस्थाओं के साथ आवश्यक समझौते किए जाने और निर्धारित बैंक गारंटी जमा किए जाने के बावजूद भुगतान नहीं होने से उन पर भी आर्थिक एवं प्रशासनिक दबाव बढ़ रहा है।पत्र में बताया गया है कि भुगतान लंबित रहने का असर एफपीओ में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, कार्यालय संचालन, किसान सदस्यों को जोड़ने के लिए आयोजित बैठकों और अन्य जमीनी गतिविधियों पर पड़ रहा है। इसके अलावा मार्गदर्शन एवं क्षमता निर्माण, निगरानी और अनुश्रवण तथा कार्यालय एवं प्रशासनिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं।किसान उत्पादक संगठनों ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के सभी लंबित प्रस्तावों का तत्काल अनुमोदन किए ।

संक्षिप्त खबरें

पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य व अजय राय ने चढ़ाई चादर

लखनऊ, (संवाददाता)। हजरत ख्वाजा मुहम्मद नबी रजा शाह दादा मियां का पांच रोजा 119वां सालाना उर्स मंगलवार को कुल शरीफ और विभिन्न कार्यक्रमों के साथ संपन्न हो गया। सुबह छह बजे आस्ताने पर कुरआनख्वानी और दुआए खैर हुईं, जिसमें बड़ी संख्या में

श्रद्धालुओं ने शिरकत की। उर्स के दूसरे और आखिरी कुल शरीफ में बड़ी संख्या में जायरीन पहुंचे। दरगाह शेखुल आलम के सज्जादानशीन नैयर मियां ने भी शिरकत कर मजार शरीफ पर फूल पेश किए। सुबह 11 बजे पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय और पूर्व सदस्य विधान परिषद क्रांति सिंह ने दरगाह पर चादर चढ़ाई। शाम छह बजे दरगाह शरीफ का गुस्ल हुआ और संदल शरीफ पेश किया गया। समापन पर कौमी एकजुटता के उनवान पर ऑल इंडिया गैर तरही मुशायरा व कवि सम्मेलन भी आयोजित हुआ।

बिजनौर पुलिस ने बाइक चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की

लखनऊ, (संवाददाता)। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बिजनौर थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध लखनऊ के विभिन्न थानों में चोरी, लूट और चोरी का माल रखने सहित कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार, पुलिस आयुक्त लखनऊ तरुण गाबा एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस उपायुक्त दक्षिणी मो. मुश्ताक के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस उपायुक्त रल्लापल्ली वसंथ कुमार तथा सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर अभिषेक कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक बिजनौर कपिल गौतम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की।मामले के अनुसार, 12 मार्च 2026 को रमेश कुमार पुत्र स्वर्गीय किशोरी लाल, निवासी जफर खेड़ा, थाना कृष्णानगर, लखनऊ ने अज्ञात चोर के विरुद्ध बाइक चोरी किए जाने की शिकायत थाना बिजनौर में दर्ज कराई थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिजनौर में मुकदमा अपराध संख्या 74ध्2026, धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।घटना के सफल अनावरण, आरोपी की गिरफ्तारी और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद करने के लिए पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देश पर दो पुलिस टीमों का गठन किया गया था।

आशियाना पुलिस ने बिजली के तार चोरी के मामले में बाल अपचारी को संरक्षण में लिया

लखनऊ, (संवाददाता)। आशियाना थाना पुलिस ने निर्माणाधीन मकान से बिजली के तार चोरी किए जाने के मामले का खुलासा करते हुए करीब 17 वर्षीय एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से पीले रंग के कॉपर तार का एक बंडल और काले रंग का एक अधजला केबल बंडल बरामद किया है। पूछताछ के दौरान बाल अपचारी से आशियाना क्षेत्र में चोरी की एक अन्य घटना के संबंध में भी जानकारी सामने आई है।पुलिस के अनुसार, मेवालाल सरोज पुत्र स्वर्गीय रामदास सरोज, निवासी सेक्टर–ओ, मानसरोवर योजना, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड, थाना आशियाना, लखनऊ ने 8 अप्रैल 2026 को थाना आशियाना में लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया था कि 27 मार्च की रात उनके निर्माणाधीन मकान से बिजली के तार चोरी हो गए थे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 97/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 305(क) में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक अग्रचारी यादव द्वारा की जा रही थी।पुलिस टीम द्वारा घटना के अनावरण और अज्ञात आरोपी की तलाश के लिए लगातार सुरागरसी–पतारसी की जा रही थी। इसी क्रम में 7 सितंबर 2026 को मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने पीडब्ल्यूडी रोड के आसपास, बंगला बाजार, आशियाना क्षेत्र में कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार मौके से मुकदमे से संबंधित चोरी का माल बरामद करते हुए करीब 17 वर्षीय एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।पूछताछ के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि यही बाल अपचारी आशियाना थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 335/2025 से संबंधित चोरी की घटना में भी शामिल रहा है। पुलिस के अनुसार दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर, आशियाना के दानपात्र से चोरी किए गए रुपये उसके द्वारा अलग–अलग स्थानों पर खर्च कर दिए गए थे।पुलिस ने बाल अपचारी को रात करीब 11रू55 बजे संरक्षण में लेकर आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी की और किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया। पुलिस के अनुसार दोनों मामलों में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।पुलिस ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मुकदमा अपराध संख्या 97/2026 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 305(क) के साथ धारा 317(4) की बढ़ोतरी की गई है।

कांग्रेस में सैकड़ों लोगों ने ग्रहण की सदस्यता, अजय राय बोले– 2027 में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे

लखनऊ, (संवाददाता)। कांग्रेस पार्टी की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए बांदा, सीतापुर, बाराबंकी और लखनऊ के सैकड़ों लोगों ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की मौजूदगी में आयोजित सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में इन लोगों ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के प्रति विश्वास जताते हुए पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। प्रदेश कांग्रेस के ज्वाइनिंग प्रभारी नितिन शर्मा ने सदस्यता ग्रहण करने वालों को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता दिलाई।सदस्यता ग्रहण करने वालों में बांदा नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष मोहन साहू प्रमुख रहे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थामा। उनके कांग्रेस में शामिल होने को बांदा में

पार्टी के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है।सीतापुर से कांग्रेस में शामिल होने वालों में दीप्ति गौतम, राजू सरोज, सेवानिवृत्त पीसीएस अधिकारी देशराज गौतम, अवध राम वर्मा और डॉ. वीबी सिंह प्रमुख रूप से शामिल रहे। इसके अलावा रामपुर के सतीश चन्द, बाराबंकी की प्रतिभा पटेल और लखनऊ के योगेन्द्र सिंह समेत कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।लखनऊ से पवन यादव, यूसुफ खान, शाकिब खान, शोएब, अब्दुल हलीम, नूर हसन कुरैशी, दिलशाद, गुफरान, वसीम, मेराज वली, अबरार, ओपी यादव, हरीश चौधरी, दलजीत सिंह यादव और रंजीत यादव सहित बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। वहीं वरिष्ठ नेता अब्दुल्ला शेर खान के नेतृत्व में बाराबंकी के मंशा राम गौतम के साथ भी बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की।सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में सीतापुर के सांसद राकेश राठौर, कांग्रेस नेता आसिम वकार, जिला कांग्रेस कमेटी लखनऊ के अध्यक्ष रूद्रदमन सिंह बबलू, अब्दुल्ला शेर खान, हनीफ खान, संजय सिंह, राकेश पाण्डेय, आदिल गौरी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

तालाब में डूबने से युवती की मौत, शौच के लिए निकली थी

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी के बाराबंकी में घर से शौच के लिए निकली युवती की तालाब में डूबने से मौत हो गई। उसका शव घर से करीब 100 मीटर दूर तालाब में उतराता मिला। घटना से परिवार में

चीख पुकार मची हुई है। घटना रामसनेहीघाट कोतवाली क्षेत्र के हथौधा गांव की है। गांव निवासी विनीता (23) की तालाब में डूबने से मौत हुई है। बताया गया कि वह शौच के लिए घर से निकली थी। पैर फिसलने से तालाब में गिर गई। वह गहरे पानी में चली गई। आसपास कोई मौजूद न होने से उसे समय पर मदद नहीं मिल सकी। जब तक लोगों को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। विनीता अपने चार भाई–बहनों में सबसे बड़ी थी।

रिटायरमेंट के बाद भी नहीं खत्म होगी नौकरी

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में सरकारी डॉक्टर अब 70 साल की उम्र तक अस्पतालों में सेवाएं दे सकेंगे। वे सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति के तहत काम करेंगे। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के तहत कार्यरत चिकित्सक 62 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। अभी इन्हें तीन साल यानी 65 वर्ष की उम्र तक पुनर्नियुक्ति के जरिये तैनात किया जाता है। इन्हें प्रशासनिक पद नहीं दिया जाता है। वे सिर्फ मरीजों का उपचार करते हैं। अब इस उम्र सीमा को 70 वर्ष किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इस संबंध में प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल्द ही अपर मुख्य सचिव स्तर से आदेश जारी हो जाएगा। इससे अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर होगी। साथ ही मरीजों को अनुभवी चिकित्सकों से परामर्श मिल सकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने पुनर्नियुक्ति संबंधी आदेश जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।

पशुपालन विभाग में छुट्टियों पर रोक, निगरानी को मंत्री खुद मैदान में उतरेंगे

लखनऊ, (संवाददाता)। पशुओं में होने वाली लंपी बीमारी नियंत्रित है, फिर भी विभाग सतर्कता बरत रहा है। विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों के अवकाश पर भी रोक लगा दी गई है। पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह झांसी मंडल और राज्य मंत्री कृष्णा पासवान जल्द ही चित्रकूट मंडल का निरीक्षण करेंगी। विभाग ने सभी 18 मंडलों में प्रदेश मुख्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया है। ये अधिकारी मंगलवार को निरीक्षण के लिए निकल गए हैं। वे 23 सितंबर तक फील्ड में रहेंगे। अपर मुख्य सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने सभी डीएम एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों को पत्र भेजा है।

काकोरी पुलिस ने छह वर्षीय बच्ची को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपा

लखनऊ, (संवाददाता)। काकोरी थाना क्षेत्र में घर से लापता हुई छह वर्षीय बच्ची को पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बच्ची के सकुशल मिलने पर परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया।पुलिस के अनुसार, मंगलवार को डायल–112 नियंत्रण कक्ष के माध्यम से सूचना मिली कि छह वर्षीय बच्ची घर से कहीं चली गई है। सूचना मिलते ही थाना काकोरी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उपनिरीक्षक शैलेन्द्र कुमार गुप्ता, उपनिरीक्षक शिवम विधूड़ी और उपनिरीक्षक विकास यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर बच्ची की तलाश शुरू कर दी।पुलिस टीम ने आसपास के क्षेत्रों में सघन खोजबीन करने के साथ स्थानीय लोगों से बच्ची के संबंध में जानकारी जुटाई। इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि रायपुर की ओर एक छोटी बच्ची को जाते हुए देखा गया है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम तत्काल रायपुर और दुबग्गा क्षेत्र में पहुंची और बच्ची की तलाश शुरू की।तलाश के दौरान रायपुर चौराहे के पास एक टेंट की दुकान के निकट छह वर्षीय बच्ची बैठी हुई मिली। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि बच्ची काफी देर से वहां बैठी थी और रो रही थी। पुलिस टीम ने बच्ची को अपने संरक्षण में लेकर उससे बातचीत की और उसके घर तथा परिजनों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। पुलिस द्वारा आवश्यक जानकारी जुटाने के बाद बच्ची के परिजनों का पता लगाया गया। आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत बच्ची को सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बच्ची के वापस मिलने पर परिजनों ने राहत की सांस ली और काकोरी पुलिस की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया।

बापू बालिका इंटर कॉलेज में छात्राओं को महिला उप निरीक्षक सोनी व श्वेता राठौड़ ने दिये सुरक्षा की जानकारी

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।महिला थाना पुलिस ने मिशन शक्ति फेज–5.0 के तहत गुरुवार को बापू बालिका इंटर कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर बालिकाओं को महिला अपराधों के प्रति सजग किया।महिला उपनिरीक्षक सोनी, महिला उपनिरीक्षक श्वेता राठौर एवं महिला कांस्टेबल रितु यादव ने छात्राओं से संवाद करते हुए उन्हें सुरक्षा,अधिकार और सरकारी योजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी दी।पुलिस टीम ने छात्राओं को विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, सुकन्या योजना तथा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बारे में विस्तार से बताया। बालिकाओं को महिला अपराधों, छेड़छाड़, उत्पीड़न सहित किसी भी अप्रिय स्थिति में घबराने के बजाय तत्काल पुलिस की सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया।इस दौरान छात्राओं को 1090 वूमेन पावर लाइन, यूपी–112, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 की जानकारी दी गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर इन हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से तत्काल सहायता प्राप्त की जा सकती है।महिला पुलिस कर्मियों ने बालिकाओं से कहा कि अपराध के खिलाफ जागरूकता ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है।किसी भी प्रकार का उत्पीड़न सहन न करें और घटना की जानकारी परिवार, शिक्षकों अथवा पुलिस को तत्काल दें। साथ ही बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ जागरूक होकर समाज में बदलाव की भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। मिशन शक्ति के इस कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं और महिलाओं को सुरक्षित वातावरण, कानूनी अधिकारों और सरकारी सहायता के प्रति जागरूक कर उन्हें आत्म विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाना रहा।

परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण में अयोध्या का उत्कृष्ट प्रदर्शन होने के चलते मिला गोल्ड मेडल

अयोध्या।परख, एनसीईआरटी नई दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित 'परखा राष्ट्रीय सर्वेक्षण–2024' में जनपद अयोध्या ने कक्षा 6 एवं 9 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है।जिसके चलते बेहतर प्रदर्शन के लिए एससीईआरटी,उत्तर प्रदेश,लखनऊ के निदेशक गणेश कुमार ने जनपद अयोध्या की टीम को गोल्ड मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।इस उपलब्धि पर जनपद अयोध्या की पूरी टीम को बधाई देते हुए शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई।सम्मान समारोह के अवसर पर अयोध्या की टीम ने आगामी परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण को लेकर अपनी कार्ययोजना भी प्रस्तुत किया।इस मौके पर डायट अयोध्या के वरिष्ठ प्रवक्ता चंद्र भूषण पांडेय, प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र सिंह, प्रवक्ता राम चन्द्र यादव, एसआरजी डॉ. अम्बिकेश त्रिपाठी तथा जिला समन्वयक निपुण रॉबिन पाल शामिल रहे।टीम ने एससीईआरटी उत्तर प्रदेश, लखनऊ में आगामी सर्वेक्षण को लेकर तैयार की गई कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण किया।

धूमधाम से निकली राधा–कृष्ण की भव्य शोभायात्रा

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।शहर में राधा–कृष्ण की भव्य शोभायात्रा धूमधाम से निकाली गई।ठठरैया मोहल्ले के लोगों ने 26वें वर्ष भी अपनी परंपरा को जारी रखा।शोभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।श्रद्धालु भक्ति गीतों पर नृत्य करते नजर आए।शोभायात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी।रिकाबगंज और सिविल लाइन होते हुए श्रद्धालु गुप्तार घाट के निर्मलीकुंड पहुंचे।निर्मलीकुंड में भगवान श्रीकृष्ण और राधा की प्रतिमाओं का विधि–विधान से विसर्जन किया गया।कृष्ण जन्माष्टमी पर शहर में कई जगहों पर राधा–कृष्ण की प्रतिमाओं की स्थापना की गई थी।कई दिनों तक पूजा–अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने उत्साह और भक्ति भाव से प्रतिमाओं का विसर्जन किया।शोभायात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए और मार्ग पर पुलिस बल तैनात रही।

'जिलाधिकारी ने जनसुनवाई में सुनीं आमजन की समस्याएं'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' गुरुवार को जिलाधिकारी अनुनय झा ने कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई करते हुए आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना। जनसुनवाई के दौरान कुल 73 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनके त्वरित निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। जनसुनवाई में विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों ने अपनी समस्याओं एवं शिकायतों से जिलाधिकारी को

कटान से जूझती सरयू किनारे की 25 हेक्टेयर भूमि बनी हरियाली की मिसाल

अयोध्या।सरयू नदी की बाढ़ और कटान से वर्षों तक प्रभावित रही रामपुर हलवारा क्षेत्र की करीब 25 हेक्टेयर भूमि अब हरियाली की नई पहचान बन रही है।कभी जलभराव और कटान के चलते अनुपयोगी नजर आने वाला यह क्षेत्र पिछले दो वर्षों के निरंतर प्रयासों के बाद अब हरे–भरे पौधों और विकसित होती वन पट्टी का रूप ले चुका है।भूमि के पुनरुद्धार और व्यापक पौधरोपण के इस अभियान में वन विभाग की सक्रिय भूमिका रही। विभाग की ओर से पौधरोपण के साथ ही पौधों के संरक्षण, नियमित देखरेख और क्षेत्र के विकास पर लगातार ध्यान दिया गया।नतीजा यह है कि सरयू के किनारे की यह भूमि अब हरियाली से आच्छादित नजर आने लगी है।खास बात यह है कि वृक्षारोपण महाभियान–2025 के दौरान इसी स्थल पर मुख्यमंत्री द्वारा 'त्रिवेणी वन' का पौधरोपण किया गया था। मुख्यमंत्री के कर–कमलों से रोपे गए पौधों समेत क्षेत्र में किए गए व्यापक पौधरोपण ने इस भूमि के हरित विकास को नई दिशा दी।सरयू के किनारे होने के कारण इस भूमि को लंबे समय से बाढ़ और कटान की चुनौती का सामना करना पड़ता था।नदी की धारा और जलभराव से मिट्टी का क्षरण होने के कारण भूमि का बड़ा हिस्सा उपयोग में नहीं आ पाता था।ऐसे में प्रभावित भूमि को पुनर्जीवित कर उसे हरित क्षेत्र के रूप में विकसित करना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।पिछले दो वर्षों में पौधों की देखरेख और संरक्षण के चलते अब यहां हरियाली लगातार बढ़ रही है। विकसित होती वन पट्टी भविष्य में मृदा संरक्षण, कटान नियंत्रण, कार्बन अवशोषण के साथ–साथ पक्षियों और अन्य जीव–जंतुओं के लिए प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। स्थानीय लोगों के लिए भी यह बदलाव आकर्षण का केंद्र बन रहा है। जिस स्थान पर कभी सरयू की बाढ़ और कटान का असर साफ दिखाई देता था, वहीं अब पेड़–पौधों की हरियाली क्षेत्र के बदलते स्वरूप की कहानी बयां कर रही है।रामपुर हलवारा की 25 हेक्टेयर भूमि का यह बदलाव इस बात का उदाहरण है कि निरंतर प्रयास और संरक्षण से बाढ़–कटान से प्रभावित जमीन को भी हरित क्षेत्र में बदला जा सकता है। सरयू किनारे विकसित हो रही यह हरित पट्टी आने वाले वर्षों में अयोध्या के पर्यावरणीय परिदृश्य को और समृद्ध करने में अहम भूमिका निभा सकती है।

अवगत कराया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय–सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त कुछ शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही समाधान कराया तथा शेष शिकायतों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट गुलाब चन्द्र सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

बालक वर्ग में राजकीय इंटर कॉलेज व बालिका वर्ग में कनौसा कान्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज ने जीती बैंड प्रतियोगिता

अयोध्या।जनपद स्तरीय बैंड प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज अयोध्या के प्रांगण में किया गया। जिसमें जनपद के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों ने प्रतिभाग किया।इस प्रतियोगिता मे बालिका वर्ग में कनौसा कान्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज,एवं बालक वर्ग में राजकीय इंटर कॉलेज अयोध्या के छात्रों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।प्रतियोगिता का आयोजन जनपद के नोडल अधिकारी अनंत कुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नोडल प्रभारी ओंकार ने विजेता टीम कनौसा कान्वेंट गर्ल्स इंटर कालेज की टीम एवं राजकीय इंटर कॉलेज अयोध्या की टीम को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया।बालिका एवं बालक वर्ग की टीम को ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया।राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अयोध्या की छात्राओं की टीम ने ने भी सांत्वना पुरस्कार के रूप में ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्राप्त किए।इस अवसर पर राजकीय इंटर कालेज अयोध्या के उप प्रधानाचार्य राम निहोर,वरिष्ठ शिक्षक एवं प्रांतीय प्रवक्ता राजकीय शिक्षक संघ राजेश कुमार शुक्ल, आनंद कुमार पाठक,श्रीप्रकाश पाल,स्काउट प्रभारी अरुण कुमार सिंह,वेद प्रकाश तिवारी,कृष्णपाल सिंह,राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अयोध्या की बैंड प्रभारी प्रीति जायसवाल,प्रीति मेहरोत्रा,कनौसा कान्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज अयोध्या की बैंड एवं स्काउट प्रभारी शिक्षिकाएं मौजूद रहीं।कार्यक्रम का संचालन राजकीय इंटर कॉलेज अयोध्या के वरिष्ठ शिक्षक धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने किया।

लायन्स क्लब जौनपुर मेन के नेत्र शिविर में 114 मरीजों की जांच, 26 मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु चयनित

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। लायन्स क्लब जौनपुर मेन एवं शंकरा आई हॉस्पिटल, वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित निःशुल्क नेत्र जांच, मोतियाबिंद ऑपरेशन एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर स्थान लक्ष्मी हेल्थ केयर सेंटर, निकट कुत्तुपुर तिराहा पर गुरुवार को सम्पन्न हुआ। शिविर में शंकरा आई हॉस्पिटल के विशेषज्ञ चिकित्सकों डॉ जियाउल हक और उनकी टीम गणेश, सुजीत, प्रिया भारती व संदीप सिंह द्वारा मरीजों की आंखों की जांच कर आवश्यक परामर्श एवं उपचार संबंधी जानकारी दी गई। 114 मरीजों की जांच हुई जिसमें 26 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन एवं लेंस प्रत्यारोपण हेतु चयनित किया गया। सभी चयनित मरीजों को बस द्वारा वाराणसी रवाना किया गया, जहां ऑपरेशन, लेंस, दवा, चश्मा, ठहरने एवं भोजन आदि की संपूर्ण व्यवस्था निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस अवसर पर संयोजक डॉ संदीप मौर्य ने बताया कि लायन्स क्लब का मुख्य लक्ष्य अंधता मुक्त समाज बनाना है, इसलिए शंकरा आई हॉस्पिटल के सहयोग से हर माह के दूसरे गुरुवार को ये शिविर इस स्थान पर आयोजित होता है। चीफ सेक्रेट्री सैय्यद मोहम्मद मुस्तफा ने बताया कि समय पर जांच से मोतियाबिंद से होने वाले अंधेपन को रोका जा सकता है। इसलिए अधिक से अधिक लोग इस शिविर का लाभ उठाएं अगला शिविर 8 अक्टूबर को लगेगा। इस अवसर पर डॉ चन्द्रकला मौर्य, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र मौर्य, डॉ अनिल यादव, अभिताष गुप्ता, राजनाथ सिंह, अजय कुमार, ममता, अंकिता, विजय कुमार विक्की सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अड़ियार कठवतीय एवं सुरेरी का निरीक्षण

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जौनपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंगाराम गौतम द्वारा गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बीसीपीएम, लैब टेक्नीशियन (एलटी) एवं एआरओ अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान डॉ. राहुल गुप्ता भी अनुपस्थित पाए गए। चिकित्सालय में साफ–सफाई की व्यवस्था संतोषजनक पाई गई तथा सभी आवश्यक औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थीं। प्रसव कक्ष के निरीक्षण के दौरान एक प्रसूता भारती भर्ती पाई गईं, जिन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। संबंधित स्टाफ को निर्देशित किया गया कि प्रसूता का जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) का भुगतान नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए यथाशीघ्र सुनिश्चित किया जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अड़ियार कठवतीय एवं सुरेरी का निरीक्षण मुख्य चिकित्सा अधिकारी जौनपुर द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अड़ियार कठवतीय एवं सुरेरी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दोनों स्वास्थ्य केंद्रों पर साफ–सफाई की व्यवस्था संतोषजनक पाई गई तथा सभी आवश्यक औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध मिलीं। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित पाए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि वे निर्धारित समय पर चिकित्सालय में उपस्थित रहें तथा स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले मरीजों को बेहतर एवं समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही मरीजों के उपचार एवं सुविधाओं में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए।

बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों को तत्काल मोटरेबल करें, लापरवाही पर ठेकेदारों पर होगी कार्रवाई – डीएम

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में निर्माण खंड–2, लोक निर्माण विभाग की सड़कों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की तत्काल मरम्मत कर उन्हें मोटरेबल स्थिति में लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि बारिश से जिन सड़कों पर गड्ढे अथवा अन्य प्रकार की क्षति हुई है, वहां तत्काल आवश्यक मरम्मत कराई जाए, ताकि आमजन को आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बरसात समाप्त होने के बाद सड़कों की स्थायी मरम्मत और ब्लैक टॉपिंग के लिए अभी से कार्ययोजना तैयार कर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं, जिससे बारिश खत्म होते ही ब्लैक टॉपिंग का कार्य शुरू कराया जा सके। उन्होंने सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्य में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न करने की हिदायत दी। संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर कार्यों का निरीक्षण करने और निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य समयसीमा के भीतर पूरा कराने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि ठेकेदारों से निर्धारित समय में मरम्मत कार्य अनिवार्य रूप से कराया जाए। कार्य में लापरवाही या समयसीमा का पालन नहीं करने पर संबंधित ठेकेदार की जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने आमजन की सुविधा और सुरक्षित आवागमन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने सड़कों से संबंधित लागत, कार्यदायी संस्था का नाम और अन्य आवश्यक सूचनाएं सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की पूरी जानकारी मिल सके। बैठक में अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग समेत अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश हुई नाकाम

सुल्तानपुर, (संवाददाता)। नगर कोतवाली क्षेत्र के पलहीपुर गांव के महेदवा में जन्माष्टमी के दिन मंदिर का चबूतरा बनाने के बहाने सरकारी जमीन कब्जा करने की कोशिश नाकाम करते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वही धार्मिक रंग देने वालों के खिलाफ भी पुलिस का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। बता दे कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन पलहीपुर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुमंत यादव उर्फ गोरे लाल यादव द्वारा अपने सहयोगियों के साथ सरकारी जमीन पर छोटी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखकर पक्के चबूतरे का निर्माण करके अवैध कब्जे की कोशिश की गई। अवैध कब्जे की जानकारी मिलते ही एसडीएम सदर गरिमा सौनकिया ने राजस्व व पुलिस टीम को मौके पर भेज कर अतिक्रमणकारियों से ही अवैध अतिक्रमण हटवाया।

विद्यार्थियों को रोजगार योग्य बनाना पीयू की प्राथमिकता

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के केंद्रीय प्रशिक्षण एवं नियोजन प्रकोष्ठ की ओर से विद्यार्थियों को रोजगार एवं बेहतर करियर के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नीरइन्फो सॉल्यूशंस के सहयोग से प्लेसमेंट ड्राइव एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बीसीए, एमसीए, बीटेक सहित विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। चयन प्रक्रिया के बाद विश्वविद्यालय के 10 विद्यार्थियों का चयन हुआ। कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह ने कंपनी के निदेशक सुधांशु शेखर और प्रबंध साझेदार वरुण महाजन से संवाद कर विद्यार्थियों के प्रदर्शन तथा उद्योग जगत की बदलती जरूरतों की जानकारी ली। कंपनी प्रतिनिधियों ने विद्यार्थियों के संचार कौशल, व्यक्तित्व विकास और उद्योग की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयारी करने पर जोर दिया। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार योग्य बनाना और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष पेशेवर तैयार करना है। विद्यार्थियों को बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण एवं नियोजन व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाएगा। रोजगारपरक प्रशिक्षण, कौशल विकास और प्लेसमेंट कार्यक्रमों का व्यापक स्तर पर आयोजन किया जाएगा।

प्लेसमेंट प्रक्रिया के प्रथम चरण में आठ सितंबर को अभिरुचि एवं योग्यता परीक्षण आयोजित किया गया, जिसमें 116 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। नौ सितंबर को कंपनी प्रतिनिधियों ने विद्यार्थियों को कंपनी के कार्यक्षेत्र, रोजगार अवसर और करियर संभावनाओं की जानकारी दी। इसके बाद व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित किए गए। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 विद्यार्थियों का चयन किया गया। समापन सत्र में सुधांशु शेखर और वरुण महाजन ने विद्यार्थियों को वर्तमान रोजगार बाजार की मांग के अनुरूप तैयारी के सुझाव दिए। उन्होंने विद्यार्थियों के प्रश्नों का समाधान भी किया। इस अवसर पर केंद्रीय प्रशिक्षण एवं नियोजन प्रकोष्ठ के निदेशक प्रो. प्रदीप कुमार, अनिकेत खरे, डॉ. नितेश जायसवाल, डॉ. दीप, डॉ. केके यादव, डॉ. अनुराग, श्याम त्रिपाठी सहित अन्य शिक्षक एवं सहयोगी उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश को वस्त्रोद्योग का देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए बड़े निवेश को उद्योग जगत उत्साहित

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश को वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में उद्योग जगत ने बड़े निवेश की इच्छा जताई है। 'यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव–2026' के उद्घाटन समारोह में पूर्व राज्यसभा सदस्य, उद्योगपति, समाजसेवी तथा रामकी समूह के संस्थापक एवं अध्यक्ष अल्ला अयोध्या रामी रेड्डी ने प्रदेश में निवेश के लिए उपलब्ध अनुकूल वातावरण की सराहना की। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे तेज विकास और बेहतर औद्योगिक वातावरण की प्रशंसा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश उद्योगों के लिए निवेश और विकास की व्यापक संभावनाओं वाला महत्वपूर्ण गंतव्य बनकर उभरा है।रामी रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उसी दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को नई सोच, अनुशासन और प्रभावी प्रशासन के साथ आगे ले जा रहे हैं। प्रदेश में सुरक्षा, स्थिरता और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था से उद्योगपतियों में निवेश का भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि उद्योगपति ऐसे स्थान पर निवेश करना चाहते हैं, जहां उन्हें सुरक्षित, स्थिर और भरोसेमंद वातावरण मिले। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ संसाधनों से भी समृद्ध है। मजबूत राजनीतिक नेतृत्व और सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था उद्योग जगत को प्रदेश में निवेश के लिए विश्वास प्रदान कर रही है।उन्होंने कहा कि वस्त्रोद्योग देश के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण उद्योगों में शामिल है। तमिलनाडु ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उत्तर प्रदेश को वस्त्रोद्योग में देश का नंबर एक राज्य बनाने के लिए तमिलनाडु सहित सफल राज्यों के अनुभवों से सीख लेकर प्रदेश की परिस्थितियों के अनुरूप ठोस कार्ययोजना तैयार करनी होगी। इसके लिए सरकार और उद्योग जगत को मिलकर काम करना होगा।रामी रेड्डी ने कहा कि लखनऊ के आसपास तथा प्रदेश के चार–पांच स्थानों पर विकसित किए जा रहे ।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।